epaper
हिन्दुस्तान

अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ा

वित्त मंत्री सीतारमण ने 1 फरवरी, 2020 को केंद्रीय बजट 2020-21 पेश करते हुए 2 घंटे 42 मिनट तक सबसे लंबा भाषण देने का रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने जुलाई 2019 में बनाए गए अपने ही 2 घंटे 17 मिनट लंबे भाषण का रिकॉर्ड तोड़ा था।

5जी के दम सेरोजगार बढ़ाने की योजना

गांवों को डिजिटल बनाने पर जोर

02/02/2022

नई दिल्ली | एजेंसी

देश में 5जी सेवाओं के लिए अनुकूल परिवेश के निर्माण के वास्ते आम बजट 2022-23 में डिजाइन संबंधी विनिर्माण योजना का प्रस्ताव किया गया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में आम बजट को पेश करते हुए कहा कि 2022-23 में 5जी मोबाइल सेवाएं शुरू करने के लिए 2022 में आवश्यक स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाएगी। सस्ते ब्रॉडबैंड और ग्रामीण तथा दूर-दराज के क्षेत्रों में मोबाइल सेवा प्रसार को सक्षम बनाने के लिए यूएसओएफ के तहत वार्षिक संग्रह का पांच प्रतिशत आवंटित किया जाएगा। सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने की 2022-23 में पीपीपी के जरिए भारतनेट परियोजना के तहत ठेका दिया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि कोविड संबंधी चुनौतियों का सामना करने में दूरसंचार क्षेत्र के उत्कृष्ट प्रदर्शन और ऑनलाइन शिक्षा एवं घर से काम (डब्ल्यूएफएच) के चलन से डेटा की खपत में भारी वृद्धि के साथ, सुधार उपायों से ब्रॉडबैंड और दूरसंचार कनेक्टिविटी के प्रसार और पैठ को बढ़ावा मिलेगा।

बजट 2022-23 में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के एक हिस्से के रूप में 5जी के लिए डिजाइन आधारित विनिर्माण के लिए एक अनुकूल परिवेश बनाने के लिए एक योजना शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है। आत्मनिर्भर भारत के विजन को हासिल करने के लिए 14 क्षेत्रों में पीएलआई को अच्छा समर्थन मिला है। इसमें 60 लाख नए रोजगार और अगले पांच वर्षों में 30 लाख करोड़ के उत्पादन की संभावना है।

स्पेक्ट्रम नीलामी मार्च के बाद: वैष्णव

दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को कहा कि 5जी स्पेक्ट्रम पर भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) की सिफारिशें मार्च तक आने की उम्मीद है, जिसके बाद अगली पीढ़ी की दूरसंचार सेवा के लिए स्पेक्ट्रम नीलामी की जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दूरसंचार विभाग जल्द स्पेक्ट्रम की नीलामी शुरू करने के लिए नीलामी से जुड़ी अन्य प्रक्रियाओं को पूरा करने पर भी काम कर रहा है।

60 लाख रोजगार पीएलआई से मिलने की आस पांच साल में

बजट घोषणा

अश्विनी वैष्णव, केन्द्रीय दूरसंचार मंत्री

ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में सस्ते ब्रॉडबैंड और मोबाइल सेवा प्रसार को सक्षम बनाने के लिए बजट में वैश्विक सेवा बाध्यता निधि (यूएसओएफ) के तहत वार्षिक संग्रह की पांच प्रतिशत राशि आवंटित की जाएगी। इससे प्रौद्योगिकी और समाधानों के अनुसंधान एवं विकास और वाणिज्यिकरण को बढ़ावा मिलेगा। शहरी क्षेत्रों के निवासियों के समान सभी ग्रामीणों को ई-सेवाओं तक पहुंच बनाने, संचार सुविधाएं और डिजिटल संसाधन उपलब्ध कराने के लिए बजट में घोषणा की गई है कि दूर-दराज के क्षेत्रों सहित सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के लिए वर्ष 2022-23 में पीपीपी के माध्यम से भारतनेट योजना के तहत ठेका दिए जाएंगे। ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम 2025 में पूरे होने की उम्मीद है।